

खबर संक्षेप

दूसरे की जगह पर परीक्षा देते सॉल्वर गिरफतार

प्रयागराज। धूमनंगज में एक बार फिर एसएससी परीक्षा के दौरान सॉल्वर पकड़ा गया। स्टेनोग्राफर परीक्षा के दौरान एक युवक दूसरे की जगह परीक्षा देते मिला जिस पर उसे पुलिस को सौंप दिया गया।

पूछताछ में आरोपी की वह अपने दोस्त की जगह पर परीक्षा दे रहा था। पुलिस ने बताया कि केंद्र प्रबंधन की तहसीर पर युवकमांदर्ज कर उसे पिरवाकर लिया गया है। 12 नवंबर को एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा आयोजित थी जिसके लिए सुलेसराय स्थित मधु वाचस्पति इंटर कॉलेज को भी केंद्र बताया गया था। परीक्षा के दौरान शक्ति और नेहरू प्रबंधन अनिल कुमार द्विवेदी ने जांच पड़ताल की तो एक युवक दूसरे की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया।

उसने खुद को मो निवासी संलग्न बताया। जिसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी

ने सच्चिद बयाकर कर दी बताया कि उसका नाम हसन यादव निवासी संलग्न, पटना बिहार है। वह अपने दोस्त मो. निजाम निवासी उत्तरामुर शोरांग की जगह पर परीक्षा देने आया। पुलिस का कहना है कि उसके कर्कने से जाली पैन कार्ड, जाली वोटर आईडी कार्ड बरामद हुआ है। यह निजाम के द्वाल दरवाजों में छोड़ा गया है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी को पिरवाकर कर जेल भेज दिया गया है।

सीडीआर व वॉइस विलप से खुल सकता है महंत के मौत का राज

जिन दो करीबियों के लेने हैं वॉइस विलप वह महंत व आनंद गिरि के भी हैं करीबी, सीबीआई को 5 लोगों की वॉइस विलप लेने की मिली है अनुमति

अखंड भारत संदेश

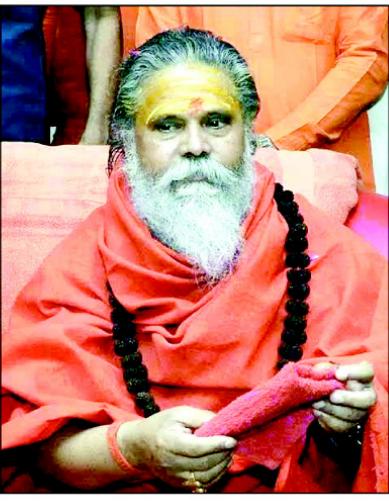
प्रयागराज। अद्यात्रा परिषद के पूर्व अव्याप्ति महंत नरेंद्र गिरि की मौत के मामले ने नामजद अरोपियों के अलावा ये अन्य लोगों का भी वॉइस सैंपल लिया जाएगा। नामजद अरोपियों के अलावा वह दोनों भी सीबीआई के रडार पर हैं और सीबीआई को जिन पांच लोगों के वॉइस सैंपल लेने की अनुमति कोटर से मिली है, उनमें वही नाम शमिल है। सीबीआई भी नाम शमिल है।

सीबीआई एक बाल द्वारा सैंपल लेने की अनुमति है।

नामजद अरोपियों के अलावा जिन दो लोगों का वॉइस सैंपल लिया जाना है, वह महंत के साथ-साथ आनंद गिरि ने भी कीरीबी है। उनकी सीबीआई से पता चला कि वह महंत के साथ-साथ आनंद गिरि के भी लगतार संपर्क में थे। आनंद गिरि के साथ उनकी बातचीत के भी कुछ अंडियां जिनमें सीबीआई के हाथ लगे हैं।

माना जा रहा है कि अंडियां विलप महंत की मौत की गुणवत्ता सुलझाने में बेहद अहम महंत सबूत साबित हो सकती हैं। यही वजह है कि अंडियां में जिन दो लोगों के बीच लगतारी है, उनमें सीबीआई ने वही नाम शमिल है।

महंत की मौत को 44 दिन बीत चुके हैं। इस तरह 19 दिसंबर तक मामले की जांच पूरी हो जानी चाहिए।



सीबीआई के पास 45 दिनों का है और वक्त

सूत्रों का कहना है कि मामले में किसी नीतीजे तक पहुंचने के लिए सीबीआई के पास ढेंड महीने का वक्त और है। दरअसल सत्त साल से ज्यादा की सजा वाले मामलों में जांच एजेंसी को 5 दिन के भीतर चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित करनी होती है।

महंत की मौत को 44 दिन बीत चुके हैं। इस तरह 19 दिसंबर तक मामले की जांच पूरी हो जानी चाहिए।

सीबीआई के पास 45 दिनों का है और वक्त

सूत्रों का कहना है कि मामले में किसी नीतीजे तक पहुंचने के लिए सीबीआई के पास ढेंड महीने का वक्त और है। दरअसल सत्त साल से ज्यादा की सजा वाले मामलों में जांच एजेंसी को 90 दिन के भीतर चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित करनी होती है। महंत की मौत को 44 दिन बीत चुके हैं। इस तरह 19 दिसंबर तक मामले की जांच पूरी हो जानी चाहिए।

असिस्टेंट प्रोफेसर के पांच मददगार शिक्षकों पर भी लटकी तलवार

अखंड भारत संदेश

स्पेक्टर - दरेगा समेत 3 पर दर्ज हो युक्त है मुकदमा

पीडिता को घटनास्थल पर बुलाकर की पूछताछ

इस मामले में जांच पड़ताल करने शुक्रवार को एक बार पिर पुलिस सीएमपी डिग्गी कॉलेज स्थित घटनास्थल पर पहुंची। इस दौरान पीडिता को भी बुलाया गया। उससे घटना के बाबत पूछताछ की गई। साथ ही कॉलेज स्टार्क से भी घटना के बाबत जानकारी ली गई। साथ ही कॉलेज प्रिंटर से वार्ता की गयी। उधर दुष्कर्म के बाबत जांच की गयी। उधर इस्पेक्टर-दरेगा समेत तीन पर दर्ज मुकदमे की जांच भी शुरू कर दी गई है। कर्नलगंज निवासी दुष्कर्म पीडिता ने मददगार वाचार व चार अज्ञात पर इसी साल 20 तक तीन पर दर्ज मुकदमे की जांच भी शुरू कर दी गई है। कर्नलगंज निवासी दुष्कर्म पीडिता ने मददगार व चार अज्ञात पर इसी साल 20 तक तीन पर दर्ज मुकदमे की जांच भी शुरू कर दी गई है।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गयी। साथ ही कॉलेज स्टार्क से वार्ता की गयी। उधर अप्रैल में जिन दो लोगों के बीच लगतारी हो गई है।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गयी। साथ ही कॉलेज स्टार्क से वार्ता की गयी।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गयी। साथ ही कॉलेज स्टार्क से वार्ता की गयी।

हाल में बंद कर अभद्रता करते हुए पूर्व में दर्ज मुकदमे में गवाही देने पर जान से मामले की धमकी दी वहाँ से जाजातान थाने जाते रहते तक 100 मीटर पहले ही रोकर जान से मामले की नीत देने के बाबत जानकारी ली गई। साथ ही कॉलेज स्टार्क से भी घटना के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता को घटना के बाबत जानकारी ली गई। साथ ही कॉलेज स्टार्क से वार्ता की गयी।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

पीडिता ने आरोपी पर लगाया है कि वह जांच करने के बाबत जानकारी ली गई।

सम्पादकीय

क्या करेंगे चिनफिंग?

यह बात गौर करने लायक है कि अब तक के इतिहास में यह तीसरा ही मौका है, जब पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया। ऐसे ही तंग श्याओं फंग अगर माओं के नेतृत्व में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान की गई गलतियों को रेखांकित करते हुए देश में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात कर सके, तो उसके पीछे 1981 में पारित इस प्रस्ताव से मिली ताकत की बड़ी भूमिका मानी जाती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के छठे प्लेनरी सेशन में पार्टी के सौ साल के इतिहास से संबंधित दस्तावेज पारित हुआ। इसे शी के राष्ट्रपति के रूप में अगले कार्यकाल की तैयारी भी माना जा रहा है। उन्हें माओ से भी अधिक ताकतवर माना जा रहा है। यह बात गौर करने लायक है कि अब तक के इतिहास में यह तीसरा ही मौका है, जब पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया। पहली बार 1945 में माओत्से तुंग के नेतृत्व में और दूसरी बार 1981 में तंग श्याओं फंग की अगुआई में पार्टी ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया था। ध्यान रहे पार्टी से पारित इस प्रस्ताव के बाद ही माओं के नेतृत्व को वह मजबूती मिली, जिसकी बढ़ावत 1949 में वह पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की घोषणा कर देश को समाजवादी रास्ते पर ले जा सके। ऐसे ही तंग श्याओं फंग अगर माओं के नेतृत्व में सांस्कृतिक क्रांति के दौरान की गई गलतियों को रेखांकित करते हुए देश में आर्थिक सुधारों का सूत्रपात कर सके, तो उसके पीछे 1981 में पारित इस प्रस्ताव से मिली ताकत की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अब जब शी ने भी वह ताकत हासिल कर ली है तो सवाल उठना लाजिमी है कि वह इस ताकत का कैसा इस्तेमाल करने वाले हैं।

जवाब का कुछ संकेत पार्टी को ओर से आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस में कही गई इस बात से मिल जाता कि यह प्रस्ताव दूसरे शतकीय लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार होगा। ध्यान रहे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने जो दो शतकीय लक्ष्य तय कर रखे हैं, उनमें पहला है 2021 तक सामान्य रूप में समृद्ध समाज (मॉडरेटली प्रॉस्परस सोसायटी) बनाना और दूसरा 2049 तक पूर्ण विकसित, अमीर और ताकतवर देश बनाना। इस दूसरे लक्ष्य को हासिल करने की चीनी नेतृत्व की बेकरारी ही है जो दुनिया के तमाम बड़े देशों की चिंता का कारण बनी हुई है। चूंकि मामला अपने समाज को समृद्ध बनाने भर का नहीं, पूर्ण विकसित, अमीर और ताकतवर देश का रूतबा पाने का है, इसलिए स्वाभाविक ही पिछले कुछ समय से चीन की अंतरराष्ट्रीय नीति में एक तरह की आक्रामकता झलकने लगी है। चाहे भारत के साथ सीमा विवाद का मसला हो या हांगकांग में लोगों के लोकतांत्रिक प्रतिरोध को दबाने का, चाहे साउथ चाइना सी में कृत्रिम द्वीपों के जरिए अपने दावों को ठोस रूप देने की कोशिशों का हो या फिर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में अपनाई जाने वाली रणनीति का- हर जगह उसकी यह आक्रामकता अन्य पक्षों को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित कर रही है। यही वजह है कि दुनिया में एक नई तरह की गोलबंदी बनने लगी है, जिसे कुछ प्रेक्षक शीत युद्ध के एक नए दौर की शुरूआत के रूप में देख रहे हैं। इसमें सद्दह नहीं कि 21वीं सदी की दूसरी चौथाई में दुनिया का स्वरूप काफी हद तक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर की इन गतिविधियों के भविष्य पर निर्भर करेगा।

उप्र : योगी का हिंदुत्व नाम केवलम

राजेंद्र शर्मा

प्रतिद्वंद्वियों पर इसके आरोप लगाने से शुरूआत कर दी थी विधि-विधान सभा के हिस्से का राशन खा जाते थे। इसके साथ ही वह यह दाव जोड़ना नहीं भूले के तब के विपरीत अब तो, अब्बा जान बोलने वालों की ऐसा कुछ करने की हिम्मत ही नहीं होगी। वास्तव में मुसलमानों को सिर चढ़ाने वाली पिछली (सपा तथा बसपा) सरकार बनाम उन्हें उनकी जगह पर रखने वाली योगी सरकार का यह प्रस्तुतीकरण, योगी के चुनाव अभियान का मुख्य प्रचार अस्त्र है बन गया है। बेशक, इस तर्क के विस्तार में लगातार नवी-नवयन सामग्रियां जुड़ती जाती हैं, पर उससे इस बुनियादी तर्क की पुष्टिदद होती है। और यह तर्क सारतः मुसलमानों को दबाकर रखने की



हिंदू हित का पर्याय बना देता है और ठीक ऐसे ही हिंदू हित वे लिए, योगी और उनकी पार्टी का साथ देने की दुहाई बन जाता है। इसी तर्क का कमाल है कि योगी, कोई न कोई प्रसंग निकालकर आए दिन अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के श्रेय की अपनी और अपनी पार्टी की दावेदारी तो दोहराते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही यह याद दिलाना भी नहीं भूलते हैं कि किस तरह उनके विरोधी ही ही मंदिर विरोधी थे! अब्बाजान प्रसंग के फौरन बाद, अयोध्या वे अपने एक दौरे पर योगी ने कार सेवकों पर गोली चलाने वाले आदि, नामों से अपने विरोधियों पर हमला बोल दिया। पुनः, तीपावलि के मौके पर सार्वजनिक कोष से लाखों दिए जलवाने के अपने विश्वरिकार्ड बनाने और हैलीकाटर से लाए गए राम-लक्ष्मण-सीता के राज्याभिषेक आदि आयोजित करने के मौके पर, योगी ने फिर अपने रामभक्त होने और दूसरों के रामदोही-रामभक्तदोही होने का बखान किया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी के अमरनाथ थाम के आयोजन के साथ जोड़कर, योगी ने फिर, वे कब्रिस्तान की दीवारों पर पैसे खर्च करने वाले बनाम हम मंदिर बनाने, उनका रख-रखाव करने वाले की दुहाई का सहारा किया। इसी बीच, सपा नेता अखिलेश यादव के स्वतंत्रता के संघर्ष के नेताओं के नामोल्लेख के क्रम में जिन्ना का नाम ले देने भर को, योगी ने अपने हिंदुत्व में राष्ट्रवाले छोंक लगाने का मौका बना लिया।

तराक से सामन जाइ, एकदम हाल के उनके मुजफ्फरनगर जैकेराना के दौरे में। मुजफ्फरनगर में अपनी सभा में, जिसमें 2013 वेदंगे के दोषी/आरोपी कई भाजपा नेता मंच पर योगी के अगल-बगल में थे, योगी ने दगों के दोषियों को पीड़ित बताकर, उनकी हिमाय

करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर योगी इन संचयी वीरों की बकालत करने पर ही नहीं रुक गए। इससे बढ़कर उन्होंने 2013 की घटनाओं की ओर सांप्रदायिक प्रस्तुति में, इस दंगे के मुख्य पैडित, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को ही हमलावर बना दिया। पर वह इतने पर भी नहीं रुके और उन्होंने यह भी बताया कि कैसे, हिंदू होने के आधार पर सांप्रदायिक गोलबंदी ही, हिंदुओं को बचा सकती है। खासतौर पर जाटों की भाजपा से मुखर नाराजगी को लक्षित कर, योगी ने बार-बार जाति की बात करने वालों पर हमला किया और लोकदल, समाजवादी पार्टी आदि, को उक्त दंगे के ही संदर्भ से, हिंदूविरोधी साबित करने पर पूरा जोर लगा दिया। बहरहाल, भाजपा का चेहरा बने आदित्यनाथ ने इतने पर भी बस नहीं की। पहले से तय कार्यक्रम से वह बगल के कस्बे, कैराना विशेष रूप से उन परिवारों से मिलने के लिए गए, जो पहले मुसलमान समाज विरोधी तत्वों के आतंक के चलते वहाँ से पलायन करने पर मजबूर हो गए थे और योगी के राज में सुरक्षित महसूस होने से वापस लौट आए हैं। योगी जी के हिसाब से इसे कश्मीर से पैदितों के पलायन का, उत्तर प्रदेश समकक्ष माना जा सकता है और वह भी इस महत्वपूर्ण अंतर के साथ कि योगी के राज में इन पलायनकर्ता हिंदुओं की वापसी हो गयी है, जबकि मोदी-शाह का राज भी कश्मीर में पैदितों की वापसी अब तक नहीं करा पाया है! बेशक, यह दुसरी बात है कि यह परा का

तक नहा करा पाया ह ! बशक, वह दूसरा बात ह एक यह पूरा का पूरा मामला ही झूठे सांप्रदायिक प्रचार का है।

कैराना से तत्कालीन भाजपाई सांसद, हुकुम सिंह ने 2016 से पहली बार इस तरह के पलायन का प्रचार शुरू किया था, जिसे 2017 के चुनाव के समय अपने प्रचार में खुद आदित्यनाथ ने खूब उड़ाला था। पर बाद में इसका प्रचार ज्यादा बढ़ने पर, डबल इंजन सरकार ने जो जांच कराई गई, उसमें हिंदुओं के पलायन के इन दावों का कोई आधार ही नहीं मिला, जिसके बाद उक्त जांच को ही दफन कर दिया गया। उस जमाने में मणिधा आई अनेक खोजी रिपोर्टों में यह सच सामने आया था कि सैकड़ों लोगों के पलायन और डर से अपने पुश्टैनी घर बेचने की सूचियां झूटी थीं और अधिकांश मामले रोजगार की तलाश में, कस्बों से शहरों की ओर, लोगों के स्वाभाविक पलायन के थे। क्या हम उम्मीद करें कि प्रत्कारों की खोजी रिपोर्टें एक बार फिर हमें बताएंगी कि इस पलायन और घर-वापसी में कितना सच है और कितना झूठ ! मुजफ्फरनगर-कैराना के आदित्यनाथ के प्रचार का यह उग्र सांप्रदायिक स्वर, इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि यह स्वर, उस क्षेत्र में आया है जो किसान आंदोलन से हुए मंथन से, योगी की पार्टी के लिए एक तरह से प्रवेश-वर्जित क्षेत्र बन गया है। यह उग्र तथा खुली सांप्रदायिक मुद्रा इसकी संकेतक है कि जनता की नाराजगी का सामना करने के लिए मोदी-शाह की भाजपा के पास एक ही हथियार है—सांप्रदायिक गोलबदी। जैसे-जैसे चुनाव प्रचार के क्रम में बढ़ते स्तर पर जनता की नाराजगी सामने आएगी, वैसे-वैसे भाजपा खुलकर इस मुद्रा में आती जाएगी, जिसके लिए ही उसने आदित्यनाथ को चुनाव के लिए अपना चेहरा बनाना तय किया है। इसके बावजूद, अगर कांग्रेस के महत्वपूर्ण मुस्लिम नेता, गुलाम नबी आजाद को, अपनी पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता, सलमान खुशर्द के यह कहने पर सार्वजनिक रूप से ऐतराज जताना जरूरी लगा है कि आइसिस आदि की ही तरह, हिंदुत्व परंपरागत हिंदू धार्मिक विश्वासों के नाम पर बोलने का दावा करने वाला, किंतु उनसे बिल्कुल अलग, एक पूरी तरह से राजनीतिक गढ़त है, तो इसे विडंबना ही कहा जाएगा। वास्तव में इस मुकाम पर आजाद का इस तरह की बहस छेड़ना कि हिंदुत्व, आइसिस आदि के मुकाबले कितना कम खतरनाक है, कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के कथित जी-23 के, जमीनी राजनीतिक-वैचारिक लड़ाई के तकाजों से बिल्कुल कटे होने को ही दिखाता है।

नोटबंदी के पांच साल : आखिर हासिल क्या हुआ?

नाटबदा के उद्देश्यों का कमा स्पृह नहीं किया गया और उसके परवता वर्षों में इस बारे में कुछ और बातें कही गईं। पहले इसे काले धन, जाली मुद्रा, आतंकवादी वित्त पोषण पर हमला बताया गया। इसके बाद यह अतिरिक्त आयकर को मोर्चिंग कर रहा था और अधिक लोगों को कर के दायरे में लाने की बात कही गई। उसके बाद कहा गया कि इसके जरिए भारत को कैशलेस ट्रांजेक्शन की ओर तेजी से आगे बढ़ने देना था। पांच साल पहले सिर्फ 4 घंटे का समय देकर देश पर नोटबद्दी थोप दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को गत 8 बजे घोषणा की कि हजार और पांच सौ रुपये के सभी नोट आधी रात से वैधानिक मुद्रा नहीं रह जायेंगे। इस घोषणा के बाद प्रभावी रूप से 86 प्रतिशत मुद्रा प्रभावी रूप से छीन ली गई जबकि उनके बदले चलने वाले नए प्रतिस्थापन नोट अभी तक तैयार नहीं थे। कई महीनों तक भारतीयों के पास अपने फंड तक पहुंच नहीं थी। शुरू में कम संख्या में जारी किए गए 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों से जनता को कोई राहत नहीं मिलते थे। शुरूआती दिनों में बैंक की शाखाओं और एटीएम के सामने सरकार द्वारा तय 4000 रुपये की छोटी सी रकम निकालने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी थीं। दैर्घ्य, बैंक स्टाफ पर हमले और लोगों की मौत के मामले भी सामने आए थे जिनमें से कुछ की मृत्यु पैसे निकालने के लिए लगी लंबी कतारों में झंटजार के दौरान हुई थी। लोगों से उनकी जमा-पूँजी छीनने का यह एक बहुत ही कड़ा और क्रूरता भरा सार्वजनिक उपाय था। 50 दिन बाद सरकार ने एक और अध्यादेश निकालकर प्रतिबंधित किए गए नोटों को अपने पास रखने को भी अपराध घोषित कर दिया। यह अध्यादेश बाद में कानून में बदल गया। बिडबना

ईवी दौड़

के रवींद्रन

हाल के महीनों में पेट्रोल की कमी का सामना करना पड़ा है, ने ईवी बाजार हिस्सेदारी में बृद्धि देखी, जो वाहन बिक्री का 22 प्रतिशत तक पहुंच गया। 2030 में गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-हाइब्रिड वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अपने कदम से पहले, सरकार ने स्थानीय वाहन नियमार्तिओं के लिए हर साल शून्य-उत्सर्जन वाहनों के बढ़ते प्रतिशत को बेचने की आवश्यकता की भी घोषणा की। जबकि दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि भारत ने एक या दो गियर नीचे कर लिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश दुनिया भर के प्रमुख ईवी बाजारों के विकास अनुमानों में भी नहीं है। यहां तक कि ईंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस की एक आशावादी रिपोर्ट का अनुमान है कि 2027 तक भारत में (ईवी) बाजार का आकार 63 लाख यूनिट मार्क प्रति वर्ष होगा। गैरतलब है कि इनमें से अधिकांश वाहन दोपहिया वाहन होंगे, जहां अपनाने की दर काफी बेहतर है। लेकिन समग्र भारतीय ईवी अपनाने की दर अगले दस वर्षों में वैश्विक स्तर पर अनुमानित 72 प्रतिशत और उसके अगले दशक में लगभग 100 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। ईवी कारों के लिए रोडमैप कुछ हद तक स्पष्ट हो गया जब मारुति के अध्यक्ष आरसी भार्गव ने हाल ही में संकेत दिया कि उनकी कंपनी मांग की कमी के कारण इलेक्ट्रिक वाहन दौड़ में शामिल होने की जल्दी में नहीं है। हालांकि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वह इस सेगमेंट में तभी प्रवेश करेगी, जब ग्राहकों के लिए वहन करने की क्षमता के साथ-साथ चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे को संतोषजनक स्तर तक विकसित किया जाएगा।

डॉ. अजीत रानाडे

मुद्रा, आतंकवादी वित्त पोषण पर हमला बताया गया। इसके बाद यह अतिरिक्त आयकर को मोर्चिंग कर रहा था और अधिक लोगों को कर के दायरे में लाने की बात कही गई। उसके बाद कहा गया कि इसके जरिए भारत को कैशलेस ट्रांजेक्शन की ओर तेजी से आगे बढ़ने देना था। पांच साल पहले सिर्फ 4 घंटे का समय देकर देश पर नोटबंदी थोप दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को रात 8 बजे घोषणा की कि हजार और पांच सौ रुपये के सभी नोट आधी रात से वैधानिक मुद्रा नहीं रह जायेंगे। इस घोषणा के बाद प्रभावी रूप से 86 प्रतिशत मुद्रा प्रभावी रूप से छीन ली गई जबकि उनके बदले चलने वाले नए प्रतिस्थापन नोट अपनी तरफ से भी नहीं आये। इसके बाद यह नोटबंदी के बाद तीन दिनों के अंदर भारतीय बैंकों द्वारा नए नोट अपनी तरफ से भी नहीं आये।

अभी तक तैयार नहीं थे। कई महीनों तक भारतीयों के पास अपने फंड तक पहुंच नहीं थी। शुरू में कम संख्या में जारी किए गए 2000 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों से जनता को कोई राहत नहीं मिली क्योंकि इस नोट के 500 रुपये के छुट्टे नहीं मिलते थे। शुरूआती दिनों में बैंक की शाखाओं और एटीएम के सामने सरकार द्वारा तय 4000 रुपये की छोटी सी रकम निकालने के लिए लोगों की लंबी लाइनें लगी थीं। दौरा, बैंक स्टाफ पर हमले और लोगों की मौत के मामले भी सामने आए थे जिनमें से कुछ की मृत्यु पैसे निकालने के लिए लगी लंबी कतारों में इंतजार के दौरान हुई थी। लोगों से उनकी जमा-पूँजी छीनने का यह एक बहुत ही कड़ा और क्रूरता भरा सार्वजनिक उपाय था। 50 दिन बाद सरकार ने एक और अध्यादेश निकालकर प्रतिबंधित किए गए नोटों को अपने पास रखने को भी अपराध घोषित कर दिया। यह अध्यादेश बाद में कानून में बदल गया। विंडबना दश का जनता खास तार पर गरब वर्ग का लग रहा था कि सरकार, इस कदम से बड़ी मछलियों को अपने जाल में फंसा लेगी। प्रधानमंत्री का संदेश यह था कि लोगों के पास जमा नगदी काला धन है और सरकार के इस अचानक किए गए सर्जिकल हमले से काला धन जमाखोर आश्र्य में पड़ जाएंगे। यदि यह घारण सही निकलती तो बंद किए जाने का अच्छा-खासा भाग बैंकों में जमा होना चाहिए था लेकिन नोटबंदी के 60 दिनों के भीतर ही यह भ्रम टूट गया था और बाद में अगस्त 2017 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इस बात की पुष्टि की कि करीब 99 प्रतिशत राशि नकदी में बदल दी गई है। बैंकिंग सिस्टम में विमुद्रीकृत राशि की यह वापसी बिल्कुल भी आश्र्य की बात नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले कई वर्षों में मारे गए आयकर छापे और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाईयों से सरकार को पता चला था कि गैर कानूनी तरीके से कमाई

गई सपात का लगभग 93 प्रश्न बनाया गया, सान, अचल सपात, स्टार्टर्स और विदेशी खातों के रूप में था। इसलिए केवल 7 प्रतिशत काला धन नकदी के रूप में बैठता है। ये सारे आंकड़े सरकार के अपने हैं। उच्च मूल्य के नोटों को बंद करना भी एक अच्छा विचार है। और्झिसीडी, यूरोपियन



ति धीमी

में है। अकेले सितंबर 2021 में चीन में 340, 000 से अधिक नए ईव्व बेचे गए, जो वैश्विक बिक्री का लगभग आधा है। चीन में ईव्वी बाजार हिस्सेदारी सितंबर में 19.5 फीसदी तक पहुंच गई। पिछले साल, बीजिंग में अधिकारियों ने सभी वाहनों की बिक्री के 40 फीसदी ईव्वी शेयर का लक्षित करने वाली एक कार्य योजना की घोषणा की, 2025 तक 25 प्रतिशत के पहले घोषित लक्ष्य को दोगुना कर दिया। हालांकि चीन वैश्विक संख्या वृद्धि का नेतृत्व कर रहा है, कई अन्य देशों में उच्च ईव्वी अपनाई की दर देखी जा रही है। उदाहरण के लिए, नॉर्वे ने अपने 100 प्रतिशत शून्य-उत्सर्जन वाहन लक्ष्य की ओर बढ़ाया रखा, जिसमें ईव्वी बाजार हिस्सेदारी सितंबर के दौरान बेचे गए सभी वाहनों के 90 प्रतिशत को पाया कर गई। इसके अलावा, जबकि टेस्ला सबसे ज्यादा बिकने वाली निमाता कंपनी बनी हुई है, चीनी ऑटोमोटिव कंपनियां बाजार में साहसर्वर्व आगे बढ़ रही हैं। जर्मनी ने सितंबर में यूरोप में सबसे अधिक ईव्वी बेचे 56,000 बिक्री दर्ज की। ईव्वी का भी जर्मन बाजार हिस्सेदारी में 30 प्रतिशत का योगदान है, जबकि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की बिक्री का प्रतिशत 38 प्रतिशत पर स्थिर रहा। फ्रांस में यूरोप में दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया करीब 29,000 ईव्वी बेचे गए, क्योंकि देश 1 मिलियन कुल ईव्वी बिक्री वें अपने 2022 लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुंच गया। फ्रांसीसी सरकार अगले साल जनवरी से बैर्ड्वी और पीएचईवी पर सब्सिडी कम करने का अपनी योजना में देरी की, उहाँसे छह महीने के लिए जुलाई 2022 तक बढ़ाया गया। यूके, जिसे हाल के महीनों में पेट्रोल की कमी का सामना करना पड़ा है, ने ईव्वी बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि देखी, जो वाहन बिक्री का 22 प्रतिशत तक पहुंच गया। 2030 में गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-हाइब्रिड वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अपने कदम से पहले, सरकार ने स्थानीय वाहन निर्माताओं के लिए हर साल शून्य-उत्सर्जन वाहनों के बढ़ते प्रतिशत को बेचने का आवश्यकता की भी घोषणा की।

ईवी दौड़ में भारत की गति धीमी

के रवींद्रन

हाल के महीनों में पेट्रोल की कमी का सामना करना पड़ा है, ने ईवी बाजार हिस्सेदारी में बुद्धि देखी, जो बाहन बिक्री का 22 प्रतिशत तक पहुंच गया। 2030 में गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-हाइब्रिड वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अपने कदम से पहले, सरकार ने स्थानीय बाहन निर्माताओं के लिए हर साल शून्य-उत्सर्जन वाहनों के बढ़ते प्रतिशत को बेचने की आवश्यकता की भी घोषणा की। जबकि दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि भारत ने एक या दो गियर नीचे कर लिए हैं, जिसके परिणामस्वरूप देश दुनिया भर के प्रमुख ईवी बाजारों के विकास अनुमानों में भी नहीं है। यहां तक कि ईंडिया एनर्जी स्टोरेज एलायंस की एक आशावादी रिपोर्ट का अनुमान है कि 2027 तक भारत में (ईवी) बाजार का आकार 63 लाख यूनिट मार्क प्रति वर्ष होगा। गौरतलब है कि इनमें से अधिकांश बाहन दोपहिया बाहन होंगे, जहां अपनाने की दर काफी बेहतर है। लेकिन समग्र भारतीय ईवी अपनाने की दर अगले दस वर्षों में वैश्विक स्तर पर अनुमानित 72 प्रतिशत और उसके अगले दशक में लगभग 100 प्रतिशत की तुलना में बहुत कम है। ईवी कारों के लिए रोडमैप कुछ हद तक स्पष्ट हो गया जब मासित के अध्यक्ष आरसी भार्गव ने हाल ही में संकेत दिया कि उनकी कंपनी मांग की कमी के कारण इलेक्ट्रिक बाहन दौड़ में शामिल होने की जल्दी में नहीं है। हालांकि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है, लेकिन कंपनी का कहना है कि वह इस सेगमेंट में तभी प्रवेश करेगी, जब ग्राहकों के लिए बाहन करने की क्षमता के साथ-साथ चार्जिंग के लिए दुनियादी ढांचे को संतोषजनक स्तर तक विकसित किया जाएगा।

जबकि अन्य निमार्ता, जैसे महिंद्रा, टाटा आदि संक्रमण की तैयारी कर रहे हैं, अंदोलन को अभी तक कर्षण प्राप्त करना बाकी है क्योंकि इंवी अपनाने के लिए शर्तों को पूरा करने के मामले में बहुत कुछ आवश्यक है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए फास्टर रेडॉशन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना के दूसरे चरण को दो साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया है। लेकिन नतीजे उम्मीद के मताबिक नहीं रहे।

में है। अकेले सितंबर 2021 में चीन में 340, 000 से अधिक नए इंवंटर बेचे गए, जो वैश्विक बिक्री का लगभग आधा है। चीन में इवी बाजार हिस्सेदारी सितंबर में 19.5 फीसदी तक पहुंच गई। पिछले साल, बीजिंग में अधिकारियों ने सभी वाहनों की बिक्री के 40 फीसदी इवी शेयर का लक्षित करने वाली एक कार्य योजना की घोषणा की, 2025 तक 20 प्रतिशत के पहले घोषित लक्ष्य को दोगुना कर दिया। हालांकि चीन वैश्विक संख्या बढ़िया का नेतृत्व कर रहा है, कई अन्य देशों में उच्च इवी अपना

है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए फास्टर रॉडाशॉन एंड मैन्युफूरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना के द्वारा चरण को दो साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दिया है। लेकिन नतीज उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे।

वैश्विक स्तर पर, ईवी की बिक्री इस साल 7 मिलियन कारों को पार करने का अनुमान है, 2020 में 3.2 मिलियन की बिक्री की दोगुनी से भी यह अधिक है। प्रमुख ऊर्जा सलाहकार रिस्टैड एनर्जी का अनुमान है कि लंग-इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन (पीएच्चीवी) और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) सहित ईवी, खरादी गई प्रत्येक 10 नई कारों में से एक के लिए जिम्मेदार होगी, जिसकी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी 10.3 प्रतिशत है। पिछले साल यह 5.3 प्रतिशत थी। यह बाजार हिस्सेदारी एक नया वैश्विक रिकॉर्ड होगा, पहली बार ईवी की बिक्री ने कुल वाहन बिक्री के दोहरे अंकों के हिस्से के लिए जिम्मेदार है, जो कि 2027 में लगभग 69 मिलियन होने का अनुमान है। ईवीएस की बिक्री ने सितंबर में ऊपर की ओर बढ़ाना जारी रखा, लगभग 700,000 इकाइयों की बिक्री हुई। ईवी बिक्री के मामले में शीर्ष 10 देशों का वैश्विक वॉल्यूम में 83 प्रतिशत का दबदबा है। सितंबर लगातार दूसरा महीना है, जिसमें वाहनों की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की बाजार हिस्सेदारी 10 प्रतिशत को पार कर गई है।

इसके साथ, 2021 की पहली तीन तिमाहियों के दौरान कुल ईवी बिक्री लगभग 4.72 मिलियन वाहनों तक पहुंच गई है। रिस्टैड एनर्जी के ऊर्जा संकरण विश्वेषक अभियोग मुरली के अनुसार, चीन में व्यापक रूप से अपनाने के कारण दुनिया भर में ईवी बिक्री वृद्धि की तीव्र दर बढ़े हिस्से में अधिकारियों ने सभी वाहनों की बिक्री का 40 फीसदी ईवी शेयर का लक्षित करने वाली एक कार्य योजना की घोषणा की, 2025 तक 21 प्रतिशत के पहले घोषित लक्ष्य को दोगुना कर दिया। हालांकि चीन वैश्विक संख्या वृद्धि का नेतृत्व कर रहा है, कई अन्य देशों में उच्च ईवी अपनावी की दर देखी जा रही है। उदाहरण के लिए, नॉर्वे ने अपने 100 प्रतिशत शून्य-उत्सर्जन वाहन लक्ष्य की ओर बढ़ाना जारी रखा, जिसमें ईवी बाजार हिस्सेदारी सितंबर के दौरान बेचे गए सभी वाहनों के 90 प्रतिशत को पार कर गई। इसके अलावा, जबकि टेस्ला सबसे यादा बिकने वाली निमाता कंपनी बनी हुई है, चीनी ऑटोमोटिव कंपनियां बाजार में साहसपूर्वक आगे बढ़ रही हैं। जर्मनी ने सितंबर में यूरोप में सबसे अधिक ईवी बेचे 56,000 बिक्री दर्ज की। ईवी का भी जर्मन बाजार हिस्सेदारी में 30 प्रतिशत का योगदान है, जबकि पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की बिक्री का प्रतिशत 38 प्रतिशत पर स्थिर रहा। फ्रांस ने यूरोप में दूसरे स्थान पर कब्जा कर लिया करीब 29,000 ईवी बेचे गए क्योंकि देश 1 मिलियन कुल ईवी बिक्री वें अपने 2022 लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुंच गया। फ्रांसीसी सरकार अगले साल जनवरी से बीईवी और पीएच्चीवी पर सब्सिडी कम करने का अपनी योजना में देरी की, उन्हें छह महीने के लिए जुलाई 2022 तक बढ़ावा दिया। युके, जिसे हाल के महीनों में पेट्रोल की कमी का सामना करना पड़ा है, ने ईवी बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि देखी, जो वाहन बिक्री का 22 प्रतिशत तक पहुंच गया। 2030 में गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-हाइब्रिड वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के अपने कदम से पहले, सरकार ने स्थानीय वाहन निर्माताओं वे लिए हर साल शून्य-उत्सर्जन वाहनों के बढ़ते प्रतिशत को बेचने की आवश्यकता की भी घोषणा की।

आग्रहम सूचना के साथ था और निश्चित रूप से यह उच्च मूल्य के नए नाट जारी करने के लिए तो नहीं ही था। अमेरिका में सबसे अधिक मूल्य का नोट 100 डॉलर का है जो उनकी प्रति व्यक्ति आय के मूल्य का 016 प्रतिशत है। 100 डॉलर के अधिकांश नोट वास्तव में अमेरिका के भीतर नहीं चल रहे हैं। उनका चलन विदेशों में ज्यादा है। भारत में 2000 रुपये का नोट देश की प्रति व्यक्ति आय का 1.3 प्रतिशत दर्शाता है। यह अमेरिका के अनुपात से 8 गुना अधिक है। चूंकि यह अमेरिका की तुलना में सापेक्ष हाइ से 8 गुना अधिक है तो अमेरिकी मानकों के अनुसार, हमारा उच्चतम मूल्य वर्ग 2000 रुपये का 1/8 यानी करीब 350 रुपये होना चाहिए। इसलिए अधिकतम 500 रुपये का नोट पर्याप्त होना चाहिए। यदि नोटबंदी का बड़ा उद्देश्य काले धन पर रोक लगाना था तो स्पष्ट रूप से सरकार इस देश में बिना रही रही है।

उद्देश्य में विफल रही है। संयोग से 8 नवंबर, 2016 से पहले 18 लाख करोड़ की नकदी पचलन में थी और पांच साल बाद 28.3 लाख करोड़ की नकदी पचलन

प्रचलन में था आपाच साल बाद 28.3 लाख कराड़ का नकदा प्रचलन में है। मतलब नकदी के प्रचलन ने 57.5 प्रतिशत की छलांग लगाई है अर्थात लगभग 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है जो वास्तविक सकल घेरेलू उत्पाद की वृद्धि से अधिक है। उच्च मुद्रास्फीति के इस वर्तमान दौर में जनता के पास मैजूद तकनी अस्थाधारणा रूप से अधिक है। यह मिशन

म जनता के पास माझूर नकदी असाधारण रूप से अधिक हा। यह इथात इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में भारी वृद्धि और यूनिफाइड पेमेंट इंस्ट्रेफेस (यूपीआई) के व्यापक उपयोग के बावजूद है। यूपीआई के जरिए हर महीने 4 अरब से अधिक का लेनदेन हो रहा है और सालाना 25 अरब का लेनदेन होगा। चीन में करीब 15 अरब का लेनदेन हो रहा है। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि भारत में डिजिटल यात्रा शुरू करने के लिए झटके

